'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 जून, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 14 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जून, 2013

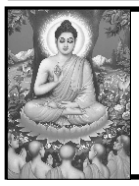

असत्य बोलने से दूर रहे।

-गौतम बुद्ध

एफवायपी के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस की बर्बरता, दलित एवं पिछड़े अति प्रभावित

गत् दिनों 3 जून को ज्वाइंट एक्शन फ्रंट फार डेमोक्रेटिक एजुकेशन (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं वामपंथी) की ओर से इंडिया गेट पर सायं 6 बजे से एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। इसकी अगुवाई डॉ. उदित राज (संयोजक), डॉ. हनी बाबू (एएसजे), डॉ. विजया वेंकटरमन (डीटीएफ), डॉ. एस. के. सागर (फोकस), डॉ. केदार कुमार मंडल (एएफएसजे), डॉ. नंदिनी दत्ता (सीटीएफ), डॉ. हंसराज सुमन (एफएएसजे), डॉ. कौशल पंवार, डॉ. सुकुमार, जी. एन. साईबाबा, पी. अब्दुल नजर (सीएफआई), विनय भूषण (एआईबीएसएफ), अनूप पटेल (एसयुआई), लेनिन विनोबर (एसएसजे) ने किया। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था कि तभी अचानक 7 बजे के आस–पास दिल्ली पुलिस बर्बरता पर उतर आयी और प्रोफेसरों (महिलाएं भी शामिल), बच्चों व छात्राओं को पीटना शुरू कर दिया और डरा–धमकाकर सभी को ले जाकर पार्लियामेंट थाने में बंद कर दिया। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने मानवाधिकार एवं प्रजातंत्र का हनन किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया। डॉ0 उदित राज ने कहा कि ऐसा करने से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है बल्कि यह लड़ाई अब और मजबूती से लड़ी जाएगी। शीघ्र ही भावी रणनीति की घोषणा की जाएगी।

इस तरह का धरना–प्रदर्शन पूरे जून माह तक आयोजित किया जाएगा। यह मामला अब यह दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि देहात, गरीब, दलित, पिछड़े आदि समाजों का भी है। अब पूरे देश के स्तर पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चार वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने के विरोध में आंदोलन छेड़ा जाएगा। डॉ. उदित राज ने कहा कि आश्चर्य होता है कि अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय ने हमारी मांगों पर ध्यान तक नहीं दिया।

गत् 19 मई को श्रीमती सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ, नई दिल्ली–1 पर प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमारी मांग नहीं मानी गयीं। इस प्रदर्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री व सचिव और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला था। हमने इनके दरवाजे खटखटाए फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के शिक्षा विरोधी अभियान अर्थात् चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करने की मुहिम को रोका नहीं गया। लगभग 700 विश्वविद्यालय देश में हैं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ही अकेले अमरीकी शिक्षा व्यवस्था का चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए आमादा क्यों है? इस तरह से सभी विश्वविद्यालय अपनी–अपनी शिक्षा नीति लागू करने लगेगें तो शिक्षा जगत में अनिश्चितता पैदा हो जाएगी। यदि देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन करना ही है तो भारत सरकार को शुरुआत करनी चाहिए न कि विश्वविद्यालय के कुलपति को। नीति निर्धारण करने का कार्य कुलपति का नहीं है। यह भ्रम फैलाना कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का मामला है, निराधार है, बल्कि कुलपति ने सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है।

पार्लियामेंट थाने में लोगों को संबोधित करते हुए माननीय डॉ. उदित राज।

यदि 4 वर्ष का स्नातकीय पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो जाता है तो छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। देहात, गरीब, भारतीय भाषी, आदिवासी, दलित एवं पिछड़े छात्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगें क्योंकि प्रथम वर्ष में 11 फाउंडेशन कोर्स पढ़ने हैं, जिसमें अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान अनिवार्य है। बहुत संभव है कि कुछ छात्र भय से प्रवेश ही न लें और लेगें भी तो बीच में छोड़ देगें। स्नातक की डिग्री में तीन स्तर पैदा हो जाएंगें, जैसे –डिप्लोमा, बैचलर एवं ऑनर्स जो छात्रों में हीनता पैदा करेगी। शिक्षकों को अग्रिम में पाठ्यक्रम को पढ़कर सुझाव देने का मौका नहीं दिया बल्कि मीटिंग के दौरान 11 फाउंडेशन कोर्स, डिसिप्लिन–1 के 18 विषय और डिसिप्लिन–2 के 6 विषय और 4 विषय अप्लाइड के पढ़कर सुझाव देने के लिए बाध्य किया गया जो इतने कम समय में असंभव था। एकेडमिक काउंसिल एवं एक्जक्यूटिव कमेटी में लोभ–लालच एवं भय से पास करा लिया गया है, लेकिन असलियत सामने तब आयी जब 12 मई को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए जनरल बॉडी मीटिंग में शिक्षकों ने इसके विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया। फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक लगातार प्रोजेक्ट आदि के द्वारा दिए जाएंगें। डिसिप्लिन–1 में 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, डिसिप्लिन–2 में भी 25 अंक और यही इन वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने का अवसर होगा तो जिस तरह से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में फेल किया जाता है और परिणाम यह हो रहा है कि छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, वही स्थिति यहां होगी। इस विश्वविद्यालय से जब ऑनर्स करके छात्र निकलेगें तो कैसे दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएंगें और उसी तरह से दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को परेशानियों का सामना दिल्ली विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा।

हम मांग करते हैं कि देश के विशिष्ट लोगों की एक समिति बने और जांच करने के बाद ही यदि उचित पाया जाए तो इस स्नातकीय पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले देश में बहस चलायी जाए और फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस शिक्षा नीति को लागू करे, यदि आवश्यकता महसूस हो तो। क्यों नहीं सरकार सोच पा रही है कि कुलपति जल्दी में लागू करने के लिए आमादा क्यों हैं? क्या यह कोई छुपा हुआ एजेंडा है? प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि इसे लागू करने में जल्दबाजी क्यों की जा रही है?

मशाल रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करती पुलिस।

वाइब्रेंट गुजरात में दलितों के लिए जगह नहीं

अर्नोल्ड क्रिस्टी

वाईब्रेंट गुजरात के सौराष्ट्र की जसदान तहसील के कनेसरा गांव में एक नन्हा सा दलित बालक अपनी दादी से कहता है, मुझे एक गिलास पानी तो दो। बहुत प्यास लगी है। वे उत्तर देती हैं, तुम अपनी मां को घर आ जाने दो। वे बहुत दूर पानी लेने गई हैं। लड़का पूछता है, मेरी मां को एक मटका पानी लाने के लिए इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है, गांव की हौदी में तो ढेर सारा पानी है। दादी को इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से मालूम है परंतु वे उस छोटे से बालक को समझा नहीं सकती।

यह संक्षिप्त बातचीत गुजरात के कुछ हिस्सों में व्याप्त अस्पृश्यता की भयावहता की ओर संकेत करती है। यह वही गुजरात है जहां की नरेंद्र मोदी सरकार बार–बार कहती है कि आल इज वेल।

उस छोटे से बच्चे की मां जया मकवाना गांव से तीन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से पानी भरकर लाती है। वह कहती है, हमारे गांव में नर्मदा का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ऊंची जातियों के लोग हम लोगों को पानी नहीं लेने देते।

जसदान तहसील के दस गांवों में लगभग 900 दलित परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र में कोली जाति का दबदबा है। दलित गंभीर जलसंकट से जूझ रहे हैं, परंतु इसका कारण सूखा नहीं वरन् जातिगत भेदभाव है। गांव में नर्मदा का पानी आसानी से उपलब्ध हैं, परंतु दलितों को उस पानी के उपयोग की इजाजत नहीं है। प्रभुत्वशाली जाति के किसानों के खुद के ट्यूबवेल हैं और उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नर्मदा के पानी की जरूरत नहीं पड़ती।

खड़वारी गांव में हैंडपंप हैं, परंतु किसी दलित को उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। दलित स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से ही गांव में हैंडपम्प यकी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एक दलित कहता है, इस गर्मी में दलित महिलाओं और बच्चों को पानी के लिए कई मील पैदल जाना पड़ता है। बाहुबली जाति के लोग हमें हैंडपम्प से पानी नहीं भरने देते। वे कहते हैं कि हम पानी तभी ले सकते हैं जब वे अपने लिए पानी भर लें।

नवसर्जन व राबर्ट के केनेडी सेंटर फार जस्टिस एंड ह्यूमन राईट्स द्वारा तैयार की गई रपट अंडरस्टेंडिंग अनटचेबिलिटी, (समझें अस्पृश्यता को) कहती है कि गुजरात में 90 प्रकार की अस्पृश्यताएं व्यवहार में हैं। दलितों को सार्वजनिक स्रोतों से पानी लेने नहीं दिया जाता, वे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते और आज भी गुजरात में 12000 से अधिक लोग सिर पर मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। वे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस और प्रशासन उनकी मदद नहीं करता। विरोध करने पर उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है।

अहमदाबाद जिले की धनधूका तहसील के गलसाना गांव में रहने वाले लगभग 100 दलित परिवारों को ऊंची जातियों के लोग उन्हें गांव के मंदिरों के प्रांगण तक में नहीं घुसने देते। इस साल फरवरी में सुरेंद्र नगर के मुली स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी कृष्णवल्लभ ने गांव के मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलवाने की पहल की थी, परंतु उनका प्रयास सफल न हो सका। ऊंची जातियों ने ऐसा नहीं होने दिया। गलसाना गांव के दलित रहवासी सुनील परमार कहते हैं, जिस दिन प्रवेश करवाया जाना था, उस दिन गांववालों और मंदिर के पुजारियों ने यह तय कर लिया कि मंदिर के पट खोले ही नहीं जाएंगे। अगर राज्य के कुछ हिस्सों में ये हालात हैं तो फिर मोदी की दलित पुजारी वाली घोषणा का क्या होगा।

सन् 2012 में न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में गुजरात दौरे पर आए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने यह पाया कि गुजरात के 77 गांवों के दलितों को सामाजिक बहिष्कार के चलते मजबूरी में अपने गांव से पलायन करना पड़ा है। जाने–माने गुजराती लेखक कानूभाई आचार्य कहते हैं, यद्यपि राज्य के शहरी इलाकों में दलितों के साथ भेदभाव में कमी आई है, परंतु गांव में अब भी यह बहुत आम है। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात के गांव में छुआछूत प्रचलित है। पिछले दो सालों से कुछ दलित परिवार दीसा के मामलतदार, तालुका स्तर के भू–राजस्व अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध–स्वरूप धरना दिए हुए हैं, क्योंकि उनका सामाजिक बहिष्कार कर ऊंची जातियों के दरबारों, अनौपचारिक अदालतों ने उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया है।

गुजरात के गांव में दलितों के शासनतंत्र का हिस्सा बनने का भी प्राणपन से विरोध किया जाता है। गुजरात सरकार की समरस योजना के अंतर्गत कमला मकवाना नामक एक दलित महिला लखवाड गांव की सरपंच चुनी गई। उनके और उनके परिवार के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दायर कर दिया गया। उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास जमानत भरने के लिए पैसे नहीं थे। हाल में एक एनजीओ की मदद से कमला को जमानत मिल सकी।

दलितों को ना केवल परेशान किया जाता है, वरन् प्रभावशाली लोगों के इशारे पर उन पर शारीरिक हमले भी होते हैं। हाल में अप्रैल में जूनागढ के मेयर को आम्बेडकर नगर में एक घर में तोड़फोड़ करने, एक दलित पर हमला करने और एक गाड़ी को आग के हवाले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

राजनीतिक–सामाजिक स्तर पर तो दलित भेदभव के शिकार हैं ही, पुलिस भी उन पर अत्याचार करने में पीछे नहीं है। सुरेंद्र नगर जिले के थानगढ़ शहर में पुलिस द्वारा किया गया गोलीचालन दलितों के विरुद्ध पुलिस के अत्याचारों का सबसे ताजा उदाहरण है। इस गोलीचालन में तीन दलित मारे गए थे, जिनमें से दो अवयस्क थे। दलित कार्यकर्ता राजू सोलंकी कहते हैं, 23 सितंबर, 2012 को विरोध–प्रदर्शन कर रहे दलितों पर गुजरात पुलिस ने कारबाइन से गोलियां चलाई। उसके पहले ना तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, ना पानी की फुहारें छोड़ी गई और ना ही आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह की कारबाईन का इस्तेमाल सन् 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले कसाब व अन्य आतंकवादी थे? राजू सोलंकी पूछते हैं। दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी कहते हैं, यद्यपि राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग ने साफ–साफ कहा है कि भीड़ हिंसक नहीं थी परंतु फिर भी पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई। आज तक पुलिस ने थानगढ़ के दलितों पर लादे गए झूठे मुकदमें वापस नहीं लिए हैं। उन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं।

गुजरात में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझकर अन्याय के खिलाफ दलितों के संघर्ष को कुचलना चाहती है। अरविंद मकवाना नाम के एक दलित युवक को पंचमहल जिले के वैद गांव में केवल चड्डी पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उसका अपराध यह था कि उसने ऊंची जाति के एक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर का किसी मुद्दे को लेकर विरोध किया था। बरासकांठा जिले के पथवाड़ा पुलिस थाने में अरविंद चौहान नामक एक दलित युवक पुलिस हिरासत में मारा गया। दशरथ सोलंकी ने ढोलका पुलिस स्टेशन के सामने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पुलिस वालों ने व्यापार में उसके साझेदार जो कि ऊंची जाति का था, के खिलाफ रपट लिखने से इंकार कर दिया था।

इन गंभीर व चिंतनीय हालातों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि गुजरात की न्यायपालिका इस तरह की घटनाओं का स्वमेव संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दे रही है।

(साभार– फॉरवर्ड प्रेस)

दलित आबादी तेजी से बढ़ रही है

भारत की कुल जनसंख्या

1,210,726,932 (1.21 बिलियन)

भारत की जनसंख्या में 2001–11 में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि पिछले दशक 1991–2001 में 21.5 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जातियों की आबादी 2011

	2011	2012	विचलन (%)
व्यक्ति	166.6	201.4	+20.8
पुरुष	86.1	103.5	+20.3
महिलाएं	80.5	97.9	+21.5

अनुसूचित जातियों की आबादी का राज्यवार विवरण–2011

सबसे ऊपर के 5 राज्य, केंद्रशासित प्रदेश

पंजाब	31.9	प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	25.2	प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	23.5	प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	20.7	प्रतिशत
हरियाणा	20.2	प्रतिशत

सबसे नीचे के 5 राज्य, केंद्रशासित प्रदेश

मिजोरम	0.1	प्रतिशत
मेघालय	0.6	प्रतिशत
गोवा	1.7	प्रतिशत
दादर और नागर हवेली	1.8	प्रतिशत
दमन और दीव	2.5	प्रतिशत

भारत की कुल दलित आबादी का लगभग आधा हिस्सा चार राज्यों में रहता है।
उत्तर प्रदेश– 20.5 प्रतिशत, बिहार – 8.2 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल – 10.7 प्रतिशत, तमिलनाडू– 7.2 प्रतिशत, नागालैंड, लक्षद्वीप व अंडमान और निकोबार द्वीपों में अनुसूचित जातियों की आबादी 0 प्रतिशत है।

16.6 प्रतिशत
दलित आबादी में 20.8 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर, भारत की 17.7 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। दलित भारत की आबादी का लगभग 16. 6 प्रतिशत है।

31 प्रतिशत
देश के 31 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है।

1,241
विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 1241 नस्लीय समूहों आदि को अनुसूचित जाति बतौर अधिसूचित किया गया है।
नोट– पिछले दशक में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूची में परिवर्तन हुए हैं।

साभार– फारवर्ड प्रेस

नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) का जन्म

1 लाख छात्र एवं नौजवानों को संगठित करने का लक्ष्य

15 प्रतिशत समाज अर्थात् ब्राह्मण, राजपूत एवं वैश्य के छात्र एवं नौजवान दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ का मामला हो या बलात्कार के खिलाफ संघर्ष करने की, कोहराम मचाकर के रख देते हैं। ऐसा क्यों नहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक एवं प्रगतिशील समाज के लोग अपने मान–सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई को लेकर के कभी बड़ा आंदोलन करते हैं। जगह–जगह पर इन वर्गों के छात्र एवं नौजवान अपने स्तर पर संगठन बनाकर कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है और ना होने वाला है। इसका मुख्य वजह यह है कि कोई राष्ट्रीय नेता और आंदोलन से ये जोड़ नहीं सके। डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पूरे देश में गत् 15 सालों से ना केवल अपनी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रखी है बल्कि मात्र एक यही संगठन है जो हर ज्वलंत मुद्दे के ऊपर मैदान–ए–जंग उतरता है। इस संगठन की स्थिति वैसी है जैसे किसी राजनीतिक दल का स्थायित्व हो। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र यदि परिसंघ से जुड़ते हैं तो उनका स्थायी प्रमुख संगठन परिसंघ हमेशा ना केवल सलाह और ज्ञान देता रहेगा बल्कि हर लड़ाई में साथ देगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए परिसंघ ने ही आंदोलन शुरू किया जिसका सीधा लाभ छात्रों और नौजवानों को ही मिलना है ना कि परिसंघ के पदाधिकारियों को। परिसंघ के आंदोलन से ही संविधान में तीन संविधान संशोधन हुआ था और आरक्षण बचा था जिसका लाभ तब से लाखों नौजवान एवं छात्र ले चुके हैं। मान लिया जाए कि छात्र एवं नौजवान अपने स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सुविधाओं एवं अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं तो क्या इससे उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? क्या मां–बाप के सपनों को वे पूरा कर सकेंगे? सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही है और ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलने से ही बहुसंख्यक छात्रों और नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इस समय सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर निजी क्षेत्र में पैदा हो गए हैं। छात्रों एवं नौजवानों का सपना नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) पूरा करेगा। सन् 2013–14 में इस संगठन के माध्यम से 1 लाख छात्र एवं नौजवान संगठित किए जाएंगे।

छात्र एवं नौजवानों को अभी तक सही दिशा दी नहीं गयी है। उनकी ज्यादा से ज्यादा संघर्ष स्कूल और कॉलेज के प्रांगण तक छात्रवृत्ति, प्रवेश, छात्रावास आदि तक की ही रहती है। चूंकि ये किसी राष्ट्रीय संगठन से नहीं जुड़े हैं इसलिए इन अधिकारों को भी हासिल नहीं कर पाते। छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा एवं तमाम समस्याओं के होने के बावजूद भी छात्र अपना सपना पूरा कर सकता है अर्थात् नौकरी जो उसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए इनकी सक्रियता प्रांगणों में चाहे कम रहे लेकिन नसोसवायएफ से जोड़ना ही मकसद होना चाहिए। क्यों नहीं एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र अन्ना हजारे एवं केजरीवाल के द्वारा संगठित छात्रों एवं नौजवानों से कई गुणा ताकतवर संगठन बनाकर संघर्ष करते हैं। कुछ छात्रों व नौजवानों को भ्रम है कि वे अपने संस्था में संघर्ष करके बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर रहे हैं जबकि यह अधूरा सच है। चाहे ज्ञान हो या संघर्ष यह तभी समाज को लाभांवित कर सकता है और रोजगार के लिए संघर्ष जब इनका भी संगठन एसएफआई, एआईएसएफ, एबीवीपी एंड एसयूआई जैसा हो। कांग्रेस का छात्र मोर्चा एनएसयूआई है और एबीवीपी भाजपा का तो उसी तरीके से नसोसवायएफ परिसंघ का है। इसे मदर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। नौजवान एवं छात्र स्कूल कॉलेज से निकलकर के जिस क्षेत्र में भी जाएगा उसको पहले से बना हुआ परिसंघ का प्लेटफॉर्म मिलेगा जैसे एनएसयूआई को कांग्रेस। कुछ छात्र एवं नौजवान स्कूल एवं विश्वविद्यालय में तमाम तरह के ज्ञान एवं विचारधारा से ओतप्रोत हैं लेकिन उनको समाज से जोड़ने वाला कोई मदर संगठन नहीं है और ऐसी स्थिति में परिसंघ के माध्यम से समाज को भी दिशा देने में सक्षम हो जाएंगे। किसी एक विश्वविद्यालय में यदि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अन्याय होता है तो वह नसोसवायएफ के ताकत का लाभ लेते हुए समस्या का समाधान जल्दी कर सकता है। छात्र–नौजवान बुद्धि विलासिता से भी छुटकारा पाकर के देश में पूरे समाज को अपने ज्ञान और अनुभव बांटेंगे। इससे इन वर्गों से पढ़े–लिखे राजनीतिज्ञ भी तैयार होंगे। वर्तमान में ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी के नेता पैर छूने वाले और चमचा पैदा हो रहे हैं क्यों कि सवर्णों की तरह इनका कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिससे सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने का प्रशिक्षण मिले। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की युवा पीढ़ी को संगठित करने का कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है जो अब नसोसवायएफ के द्वारा किया जाएगा।

कुछ लोग तमाम प्रतियोगिता के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि चलाकर के समझ रखते हैं कि बुद्धि एवं ज्ञान विकास से नौजवानों एवं छात्रों का कल्याण हो जाएगा लेकिन यह अधूरा सच है। दलित, आदिवासी एवं ओबीसी अब ज्यादे पढ़े–लिखे नौजवान हैं और उस अनुपात में सरकारी नौकरियां बढ़ना चाहिए लेकिन घटी हैं। ऐसे में चाहे जितना प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर ली जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4–5 प्रतिशत लोग ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, सिपाही, स्टेनो आदि बन सकते हैं और बांकि को तो बेकार होना ही है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई इन समाजों का संगठन है भी नहीं जो फूले, शाहू एवं डॉ. अम्बेडकर के विचारों का हो और वह प्रयोगशाला बन सके कि यदि सभी छात्र प्रतियोगिता में सफल नहीं होते तो और भी क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए चाहे वह सामजिक नेतृत्व हो या राजनीतिक। निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन बढ़ गया है इसलिए वहां आरक्षण के बगैर ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई–लिखाई बेकार हो रही है। हमारे समाज में व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियां करने का संस्कार नहीं है और परिसंघ ने तय कर लिया है कि राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काफी कार्य हो चुका है और हो भी रहा है और अब शुरुआत करनी है आर्थिक क्षेत्र में। नसोसवायएफ इस आंदोलन को चलाने में सहयोगी भूमिका अदा करेगी ताकि जो छात्र नौजवान नौकरी एवं राजनैतिक एवं सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं तो व्यापार की दुनिया में कदम रखते हुए सपने पूरा करेंगे।

आजादी के बाद का इतिहास रहा है कि जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र संगठन रहे हैं, उन्होंने कभी हमारी समस्याओं को लेकर के संघर्ष नहीं किया। यह सर्वविदित है कि ज्यादातर छात्र संगठनों पर मनुवादियों का ही कब्जा रहा है और है भी तो वे क्यों हमारी बात करेंगे। सवर्णों ने हजारों वर्ष से भेदभाव किया है और अभी वह जारी है तो ऐसे में हमारा निज का संगठन होना जरूरी है जो अभी तक हुआ नहीं है। कुछ सवर्ण छात्र भी प्रगतिशील एवं अंबेडकरवादी हैं तो उनके लिए हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे।

1 लाख नौजवान और छात्रों की ताकत में जो जितना सहयोग देगा वह समाज का बहुत बड़ा कर्ज उतार सकेगा। हम सबके ऊपर समाज का कर्ज है और उसे उतारना चाहिए। जिसे भी यह सूचना मिले वह ज्यादा से ज्यादा छात्रों व नौजवानों को इस संदेश को देते हुए नसोसवायएफ का सदस्य बनवाये। हर व्यक्ति का योगदान लिखा जाएगा कि किसने 1 लाख की संख्या को पूरा करने में कितना सहयोग दिया।

विनीत
हर्षवर्धन–07709975562,
ईमेलः
h.dawane2013@gmail.com
आर. सी. बदोट (राज)
09829299092
ईमेलः
raj_udaipur84@rediffmail.com
नितीन गायकवाड
09028200358,ईमेल :
nitinvijayg@gmail.com
गणेश बाघमारे
09270055151

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

सच बोलूं तो बुरा

डॉ. उदित राज

सुश्री मायावती की कार्यप्रणाली यदि जनतांत्रिक हो तो उन्हें 70 से 100 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। इसके लिए उन्हें अपने में बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह से और नेता अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों एवं सांसदों से मिलते हैं और सुझाव भी लेते हैं, वैसा इन्हें भी करना पड़ेगा। दलित समाज की रीढ़ कर्मचारी–अधिकारी हैं। ये देनेवाले हैं ना कि कुछ चाहते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर हैं। कभी–कभार इनके साथ भेदभाव होता है तो इनकी बात सुनी जाए और निवारण करने का प्रयास किया जाए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा की रोजाना प्रेस कांफ्रेंस होती है उसी तरह से ये क्यों नहीं करते? देश में प्रतिदिन कहीं ना कहीं बलात्कार एवं उत्पीड़न होता है, आरक्षण पूरा नहीं किया जाता, ट्रांसफर–पोस्टिंग में भेदभाव होता है, गलत नीतियां बनती हैं, यदि इसे मीडिया के माध्यम से रोज उठायीं जाएं तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम लागू कर दिए। दलित–पिछड़े शिक्षक, छात्र एवं बुद्धिजीवी बहुत कोशिश किए कि सुश्री मायावती उन्हें समय दें ताकि मिलकर के बता सकें कि इस शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा के दरवाजे धीरे–धीरे बंद कर दिए जाएंगे। भाजपा, सीपीएम, जनता दल यू, लोकजनशक्ति पार्टी, सीपीआई आदि ना केवल प्रतिनिधियों से मिले बल्कि खुलकर के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के विरूद्ध बोले भी। भाजपा के श्री अरूण जेटली ने मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर के रोक लगाने की मांग की तो जनता दल यू के अध्यक्ष श्री शरद यादव ने भी ऐसा किया। सीताराम येचुरी प्रधानमंत्री से मिले। जो कार्य बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए था, वो काम दूसरों ने किया। इससे सर्वाधिक हानि दलितों व पिछड़ों को ही होना है। बसपा के लगभग 40 सांसद हैं और यदि प्रत्येक को काम करने की आजादी दी जाए तो देश में उत्पीड़न भी कम होगा और समाज आगे भी जा सकेगा। अधिकारों की सुरक्षा होगी और जहां–जहां भागीदारी नहीं है वहां भी संभावना बढ़ेगी।

आज दलित समाज की हालत ऐसी हो गयी है कि जैसे कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दूसरी पार्टियां भीतर–भीतर गुस्साए बैठी रहती है कि दलितों का वोट तो उन्हें मिलता नहीं तो वे क्यों पहले के जमाने की तरह काम करें। कहीं–कहीं पर ये कह भी देते हैं कि जाओ बसपा से काम करा लो। बसपा का दरवाजा बंद रहता है और सांसदों, विधायकों एवं नेताओं को जनसमस्याओं को उठाने की इजाजत भी नहीं है ऐसे में लोग कहां जाएं ? मेरे इस बात से बसपा के लोग नाखुश होंगे लेकिन यह हकीकत है और जिन लोगों को बुरा लगे तो उन्हें जाकर के अपने नेता से बात करना चाहिए। इससे वे आजमा भी लेंगे जो मैंने सही कहा या गलत। मुझे मालूम है कि पूरे देश में से एक बसपाई की हिम्मत नहीं है कि वे जाकर के उपरोक्त सुझाव सुश्री मायावती को दे सके। हर तकलीफ, दर्द, अधिकार हनन एवं समस्या का एक ही जवाब है कि जब हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे? क्या दूसरे पार्टी के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा कहते हैं? जिस दिन वे करें, पार्टी टूट जाएगी लेकिन बसपा कार्यकर्ता महान हैं कि वे बगावत नहीं करते हैं। इस तरह से महानता कार्यकर्ता की है ना कि सुश्री मायावती की। यदि सुश्री मायावती उपरोक्त सुझावों को मानने के लिए तैयार हों तो मैं बसपा का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हूं क्योंकि यह समाज हित में है। समाज हित में जो भी कुर्बानी देने पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूं। यदि किसी बसपाई में हिम्मत है तो अपने समाज के हित में यह कार्य क्यों नहीं करता ?

... तो पति को है पिटाई करने का स्वाभाविक हक

हिमांशु मिश्र

घरेलू हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में चल रही मुहिम के बीच खुद महिलाओं ने पति के हाथों पिटाई को मौन स्वीकृति दे डाली है। यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण में यह कड़वा सच सामने आया है कि दुनिया की 47 फीसदी ना सिर्फ पति की डांट–फटकार बल्कि पिटाई को भी जायज मानती है।

भारत की स्थिति तो और भी जटिल है। यहां की 54 फीसदी महिलाएं मानती है कि कुछ मुद्दों पर पति को पत्नी को पिटाई करने का हक है। मुद्दे भी मामूली हैं। मसलन समय पर खाना ना देना, खाने में नमक तेज होना, पति के घर पहुंचने पर तत्काल पानी ना देना। यूनिसेफ ने महिलाओं की स्थिति पर बीते एक दशक में दुनिया भर में हुए सर्वेक्षणों का दिलचस्प आंकड़ा जारी किया है। इस मामले में सर्वाधिक बुरी स्थिति अफगानिस्तान और जॉर्डन की है। इन देशों की 90 फीसदी महिलाएं कुछ मुद्दों पर पति की पिटाई और डांट–फटकार को बुरा नहीं मानती। समाजशास्त्रियों का मानना है कि इसके पीछे पालन–पोषण के दौरान परिवार के माध्यम से मिले संस्कार हैं, जहां पति को बहुत ऊंचा ओहदा मिला हुआ है। इस संबंध में यूनिसेफ ने वर्ष 2002 से वर्ष 2011 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा महिलाओं की स्थिति पर दुनिया भर में किए गए सर्वेक्षणों के नतीजे जारी किए हैं। इस मामले में सर्वाधिक बुरी स्थिति दक्षिण एशियाई देशों की है। पूरे दक्षिण एशिया की 52 फीसदी महिलाएं और 49 फीसदी पुरुष पत्नी की पिटाई को बुरा नहीं मानते। समाजशास्त्री प्रोफेसरर इम्तियाज अहमद और रजनी नागपाल इसके लिए पारिवारिक संस्कार को जिम्मेदार ठहराते हैं।

राजस्थान के प्रत्येक जिले में नसोसवायएफ की बैठक का दौर शुरु

हर्षवर्धन दवणे

नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) राजस्थान में छात्र संघ एवं युवा संघ बढाने का प्रयास कर रहा है। यहां पर दलित एवं आदिवासी छात्रों के लिए राज्य सरकार का कोई छात्रावास नहीं होने के कारण गांव और देहातों के छात्र शहर विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहां पर प्राथमिक शिक्षा नीति में बहुत से सुधारों की जरूरत है। वर्तमान की राजस्थान शिक्षा नीति दलित एवं आदिवासी छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखने की है। राज्य में जिला एवं विश्वविद्यालय स्तर पर दलित एवं आदिवासियों के बहुत छात्रसंघ है मगर उनमें एकता नहीं होने के कारण दलित एवं आदिवासी छात्र एवं युवाओं की ताकत बिखरी हुई है। उसी तरह राज्य में दलित एवं आदिवासियों का शोषण भी बढ़ रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर राजस्थान में नसोसवायएफ छोटे–छोटे छात्र संगठन और युवाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर दलित एवं आदिवासी युवा छात्रों की एकता मजबूत करने के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। राज्य के नसोसवायएफ के नेता और राष्ट्रीय संयोजक राज बड़ोत और श्री हर्षवर्धन राजस्थान के विभिन्न जिलों में छात्र एवं युवाओं की बैठक कर रहे हैं। जिला बासवाड़ा, ढ़ोंगरपूर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अन्य जगह में भी बैठक हुई है। छात्र एवं युवाओं का सहयोग संगठन के प्रति राजस्थान में बढ़ता जा रहा है।

बैठक को संबोधित करते श्री हर्षवर्धन दवणे।

इंजपा जिला कमिटी गठित

गत् दिनों 8 जून को मशाल डैम्प परिसर, रामनगर में इंडियन जस्टिस पार्टी (इंजपा) की कार्यकारिणी बैठक प्रदेश उपसचिव भागीरथी राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर श्री प्रशेष शर्मा को सदस्यता ग्रहण व अनुमंडल अध्यक्ष, बगहा के पद पर मनोनीत कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही पार्टी के संगठन मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। इस मौके पर सुधीर कुमार (जिलाध्यक्ष, पश्चिमी चंपारण), रामप्यारे राम (अनुमंडल अध्यक्ष, नरकटियागंज), गौरीशंकर दुबे (विधानसभा अध्यक्ष, नरकटियागंज), सुरेंद्र मिश्र, रोशन राम व मो. इरशाद उपस्थित थे।

Dalit Population Growing Faster

1,210,726,932 (1.21 BILLION)

TOTAL POPULATION OF INDIA

Population of India grew by 17.7% during 2001-2011, against 21.5 % in the previous decade (1991-2001).

Population of SCs : 2011

	2011	2012	Variation (%)
Persons	166.6	201.4	+20.8
Males	86.1	103.5	+20.3
Females	80.5	97.9	+21.5

States/UTs Ranked by proportion of SCs-2011

Top 5 States/UTs

States/ UTs	In Percentage
Punjab	31.9
Himachal Pradesh	25.2
West Bengal	23.5
Uttar Pradesh	20.7
Haryana	20.2

Bottom 5 States/UTs

Mizoram	0.1
Meghalaya	0.6
Goa	1.7
Dadra & Nagar Haveli	1.8
Daman & Diu	2.5

Nearly Half of the country's dalit population lives in Four States

Uttar Pradesh- 20.5 %, Bihar - 8.2 %, West Bengal - 10.7 %, Tamilnadu - 7.2 %

0%

Nagaland, Lakshwadeep and Andaman and Nicobar islands : 0% SCs

16.6%

Dalit population showed a decadal growth of 20.8 % (higher than India's 17.7%). Dalits from around 16.6% of India's population.

31%

Scheduled Castes (SCs) are notified in 31 states/UTs of India

1,241

There are altogether 1,241 individual ethnic groups, etc. notified as Scheduled Castes in different States/UTs.

Note-There has been some changes in the list of SCs/STs in States/UTs during the last decade.

Courtesy- Forward Press

I am Condemned for Speaking the Truth- Udit Raj

Dr. Udit Raj

It is not the upper caste people but people from dalit community who have branded and defamed me as an agent of BJP and Congress. This news is not only taking rounds as a rumour in different parts of the country but a large number of people have believed also. I have now started realizing that it is not always the truth which wins. Normally, a man becomes an agent for two reasons, one for money and the other is for power. As far as money is concerned, I kicked the job of Additional Commissioner of Income Tax for the welfare and development of the deprived and downtrodden people of the country. If I wanted to make money, there would have been nothing better than the job of the Additional Commissioner of Income Tax rather than to go and beg from parties like BJP or Congress. As regards power, had any of these two parties given me some important post, everybody would have known about it. This has not only damaged me but also to the society . Had I entered the Parliament, then our community would not have regretted the fact that there is no effective speaker in the Parliament who can espouse their cause and raise burning issues like reservation in promotions, permission for FDI investment in retail trade, Delhi University 4-year undergraduate course, etc. Introduction of Delhi University 4-year Hons Degree Course is a conspiracy to deprive Dalit, Adivasi and OBC students of the opportunity of higher education. Even by remaining outside the Parliament, I am more effective than ten MPs to raise demands and voice as far as Dalit/Adivasi/OBC/ weaker section issues are concerned. If I had been a Member of the Parliament, I would have carried more weight than the present total strength of 131 SC/ST/OBC Members of Parliament. In every nook and corner of the country, people are saying that I am diluting the strength of Mayawati Ji. Does it imply that there should be only one Dalit leader in the country. Nobody knows for how many years one shall live. One can die any moment and in such an event, should there be only one Dalit leader in the country? Unfortunately, if something happens to such a single Dalit leader, then Dalits shall remain without a leader. People very well know it that after the demise of Baba Saheb, Dalit community remained without a leader for several years. Baseless and illogical allegations are made against me for having formed a political party. It is also known to everybody that the population of upper caste people is much less than the population of SC/ST/OBC people. Despite this, the upper caste people are having several parties and leaders. Then, there is no reason why Dalits cannot have more than one leader and one party. I am ready to meet Mayawati on the issue of reservation in promotions but is there any leader in BSP who can arrange this meeting or shall I take it that when I personally contact her, she will react positively on the issue? In these circumstances, supporters of Mayawati, who are never tired of blaming me for pulling her down, as to how I am damaging her stature. Anybody who is bold enough on this issue should openly come forward and give a reply or make some useful suggestion. In the interest of society, I am ready to do anything.

Dr Kaushal Panwar made this statement on 11 June in Human right Council, Geneva on behalf confederation

All India Confederation of SC/ST Orgainsations has been raising the voices of weaker section in Human Right Council , Geneva for last 3 years and this time it is Dr. Kaushal Panwar, Associate profeesor in Delhi University who was sent to represent.

Untouchabiltiy is the most obnoxious forms of discrimination which is still widely prevalent in India and has the sanction of Hindu religion. Hinduism ordains that all human beings are not born equal as Brahmins are born from the mouth of God, Kshatriyas from God"s arms, Vaishyas (business community) from God's belly and the bottom are untouchables who are born from God's feet. This has led to caste-based discrimination against Dalits, inhuman living and working conditions, impoverishment, mal-nourishment, high levels of illiteracy and continuing social ostracism and non-entry into temples. The situation regarding social discrimination is so desperate that even a highly placed public figure holding a constitutional post was denied entry into the Jagannath Puri temple recently. The situation in rural India for untouchables is much worse as they are deprived of social activities like sharing of water, food and drinks. They are publicly dehumanized for very petty crimes . Most of untouchables continue to live in extreme poverty. A single hour or day does not pass when they are not killed, burnt, raped and their houses, properties and land are not destroyed or usurped. Most of the untouchables continue to live in extreme poverty, without land and they lack for better employment and education. The situation is so bad that on an average, two Dalits are assaulted every hour, three Dalit women are raped, two Dalits are murdered and at least two Dalits are tortured or burned every day. Two dalits were burnt alive in Mirchpur ,Haryana state and a large number of Dalit families ran away from their homes and hearths in shock and fear. In another horrendous incident in Jhajjar district of Haryana, India, five untouchables (Dalits) were lynched by a large mob of upper caste Hindus because they had allegedly skinned a cow which is considered holy by the Hindus. In yet another incident, a four-month pregnant Dalit woman from a district in the State of Tamil Nadu in India, was beaten by upper caste Hindus from the same village. She was stripped naked and paraded in front of villagers and her family members. Later, police beat her in jail which resulted in her miscarriage. As regards atrocities against Dalits, out of 10 cases of atrocities against Dalits, only one is prosecuted. It is because of the mind-set of the judiciary which is still controlled mostly by the upper-caste judges. A dog of upper caste fed by dalit woman in Muraina, MP became impure and was thrown out of home and she was penalized.

There is rampant discrimination in Government in the matter of recruitment and promotions. Over-all the condition of untouchables (Dalits) is so bad that the upper caste Hindus whose population is not more than 15% control 85% of the wealth, power, judiciary, and 100% of the newly emerged sectors like Information Technology, Construction, Telecommunication ,Service Sector, Capital/Share Market. In the matter of education, dalit women are far behind as compared to the women of other castes and there has been little progress in decreasing the education gap between Dalit females and the females from upper castes.

Whatever progress dalits made up to now, getting reversed on account of globalization and privatization. World community is also kept in dark that these all are due to spirituality , in other word, this is the way of life and outsiders have no business to interfere . Though the dalit issue is getting globalized but pace is very slow and we urge the UN Human Right Council to pay more attention to this.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

New Education Policy to Deprive SC/ST/OBC from Higher Education

Dr. Udit Raj

Experiment is welcome but it should not be for worse. Delhi University is hell bent upon introducing a four-year undergraduate programme (FYUP), a departure from national education policy of 10+2+3. Education Policy is to be decided through participatory deliberations by legislature and the government and the UGC is standardization body. A university cannot initiate the move to change the policy and if all 600 universities start making their policies, there

will be utter chaos and dire consequences. If the Vice Chancellor is bubbling with energy to do something then the priorities should be to implement reservation in teaching, to carry forward the unfinished task of his predecessor to improve the quality of the affiliated colleges and other institutions, to balance the teacher and student ratio, and to create other infrastructure and hostel facilities.

All opposition is being brushed aside terming it a left move. In fact, now more concerns have been raised by SC/ST/OBC communities, and that is why the Joint Action Front for Democratic Education (SC/ST/OBC/LEFT) came into existence in May to oppose FYUP. Various representations and delegations to different authorities like the Minster for Human Resource Development, the Prime Minister, and the President, and yet there is no reconsideration. What forces are behind this move? One can speculate, and obviously the ground is being made ready for privatization of higher education. The most affected will be SC, ST and OBCs, not only because of increased financial burden, but also on many counts like course contents, internal assessment and background. Instead of increasing the duration of the programme, attempts should be made to enrich the course contents. Private colleges and universities have more elasticity to adopt FYUP, and that will escalate the privatization and these communities will be the worst affected. Higher education in India is associated with a myriad of values like higher social status, high income, better job and more access to different ways and means. This is not the case in the US. The FYUP will not only precipitate more dropouts, but it will also make Higher education inaccessible to these communities.

Majority of the people now are questioning the wisdom of the vice chancellor who has demanded FYUP. The manner in which the university is hastening to implement it without debate, smells of something. This is the structural change in the education policy which needs to be debated at National level in consultation with all the stakeholders, which would then have to be adopted by the MHRD. It is the height of audacity on the part of VC, who is now questioning those who are raising genuine issue. Offence is the best policy to protect one's act and that is why the VC has slammed those who have questioned his power to change the education policy. At no point, there is assurance to execute it successfully and for that it needs proper preparation. The Academic Council is being used as a rubber stamp and all kinds of ways and means have been adopted to silence the sane voices. However, May 12 rebutted the claim of support, when Delhi Teachers General Body meeting unanimously rejected FYUP.

There are a number of contradictions: how the holders of three years degree from other universities will get admission in DU and how the holders of four-year degree from DU will pursue further studies in other Indian universities; the course contents of other universities will be different and how that will be reconciled; will it not create discrimination in getting the jobs; will it not be difficult for rural and Indian languages background students to study compulsorily Maths, Science and English; will it not encourage inequality in the same degree with the multiple exit points, i.e., diploma at two years, bachelor at three and honours degree after four years.

The students will have to study 42 papers – 11 foundation courses, 20 papers in their first discipline, 6 papers in the second discipline, and four in applied and this will dilute the knowledge and understanding of subjects and thus creation of boogey of students who will be master of none and jack of all.

The VC is crying hoarse that FYUP has potentiality of employability and it is yet to be tested. The students of this programme will have better prospects of employment. But how can it be believed? There have been similar initiatives in the past when an atmosphere was created that the country should go for technical and professional education, and as a result millions of engineers and management degree holders were produced but what happened eventually? Hundreds of private professional institutions were opened in places like Andhra Pradesh and elsewhere, and and it saying over there- one cannot afford not to become an engineer . Most of them are unemployed and are ready to work with meager salary and product of FYUP will eventually land up in same state.

There is also a conspiracy to halt India to become biggest knowledge society and the FYUP is one of the mechanisms to fulfill the design of West and US. Our apprehension is that FYUP will influence higher education policy in the country, which will have adverse an effect on the interest of the SC/ST/OBCs, who are just entering the field of higher education.

Rest of Page 8 ...

Highhandedness of Delhi Police against peaceful protestors of Joint Action Front for Democratic Education

course. It is also not clear as to how the Honors students of the 4-year degree course from Delhi University will seek admission in other Universities and vice versa.

We demand that a Committee of Eminent Persons is constituted for this purpose and after an in-depth study of the the matter, the four-year course may be introduced, if it is deemed fit. The best course would be to hold a discussion across the country on this issue and then the Ministry of Human Resource Development may formulate and introduce a policy on this matter, if it is considered necessary. Why is the Government not probing the fact as to why the Delhi University Chancellor is hell bent to introduce the four-year course in such a big haste? Is there any hidden agenda? Yes?

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 14 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 June, 2013

असत्य बोलने से दूर रहे।

-गौतम बुद्ध

Torchlight Protest against FYUP

A large number of people gathered at India Gate on 03.06.2013 to carry out torchlight protest against the implementation of four years undergraduate programme (FYUP) in Delhi University. The Joint Action Front for Democratic Education(SC/ST/OBC/Left) was constituted to fight it out . JAFDE is represented by Dr. Udit Raj (Convener), Dr. Hany Babu (ASJ), Dr. Vijaya Venkataraman (DTF), Dr. S. K. Sagar (FOCUS), Dr. Kedar Kumar Mandal (AFSJ), Dr. Nandini Dutta (CTF), Dr. Hansraj Suman (FASJ), Dr. Kaushal Panwar, Dr. Sukumar, G. N. Saibaba, P. Abdul Nazar (CFI), Vinay Bhushan (AIBSF), Anoop Patel (SUI), Lenin Vinober (SSJ.Participants were forcibly dragged and taken to the Parliament Street police station. The police snatched the placards, manhandled women, disabled persons on wheel chairs and children. The protestors were not even allowed to hold a torchlight protest. Join Action Front condemns this brutal attack on peaceful protestors against anti-people and anti-poor policies of the government. The Front demands the roll back of FYUP immediately.

The Joint Action Front for Democratic Education is planning a series of agitations as the government is refusing to intervene and stop the implementation of FYUP. More and more intellectuals and organizations of SC/ST/OBC are joining the protests. Government has to realize that FYUP is not an internal matter of Delhi University as it is going to affect thousands of students. The MHRD cannot ignore the voice of the masses and refuse to take any action. In spite of our demonstration on May 19th at 10 Janpath, New Delhi (Smt. Sonia Gandhi's residence) our grievances were not addressed by the Government. We were forced to demonstrate as the Prime Minister, HRD Minister, or UGC did not take any steps. The Prime Minister showed the concern for the hurry to implement four year undergraduate programme, but that again has not stopped the move of VC. There are about 700 Universities in the country and it is only Delhi University which is bent upon introducing 4-year degree course based on the American pattern of education. If at all, education policy of the country needs to be changed, the initiative for the same should come from Government of India and not the VC of a particular University. Policy formulation is not the job of a VC. It is highly misleading and baseless on the part of the Delhi University VC to say that it falls within the autonomy of University. In fact, the VC has flagrantly encroached upon the domain of the Government to frame policies. If the 4-year degree course is introduced in Delhi University, it will have an additional financial burden on the students. Students from Dalit, Adivasi and Backward categories, poor students from rural and urban areas and students passing out with regional languages as their medium of instruction, will be hit by this course to the maximum. It is very likely that some students may not seek admission to this course out of a sense of fear and even when they muster the courage to join such a course they may end up dropping it mid-session. Currently dropout rate in higher education of SC/ST is 30% and with this, it may scale up to 50%. This encourages the inequality in the same degree, i.e., Diploma, Bachelor and Honors which will create a sense of inferiority complex among the students. Teachers were not given an opportunity to go through the proposed syllabi before giving their suggestions and during the meeting, they were forced to give their suggestions on 11 Foundation Courses, 18 subjects of Discipline I, six subjects of Discipline 2 and four applied subjects which was next to impossible in such a short span of time. If these communities are stopped at lower level, they will be further marginalized and unlike USA, here higher education degree is more connected with dignity, income, status and participation. Members of Academic Council and the Executive Council of Delhi University were offered so many incentives and pressurized to pass the resolution on the 4-year degree course but the truth came to the surface when a large number of teachers from Delhi University passed a resolution against the 4-year course at their general body meeting on 12.5.2013. In the Foundation Course, 35 marks will be allocated for continuous projects, in Discipline I, 25 marks will be allocated for internal assessment, in Discipline II, 25 marks will be allocated for internal assessment and it is precisely this methodology also that will be used for discrimination against the SC/ST/OBC students. It is because of this pattern of evaluation that the SC/ST/OBC of Engineering and Medical students are made to fail in the examinations resulting in suicides and what not. The same situation will prevail for SC/ST/OBC students in the proposed 4-year degree

Rest on Page 7 ...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn